नई दिल्ली, बुधवार
12 सितंबर 2018
गाजियाबाद
मूल्य ₹ 4.00
पृष्ठ 20+6=26

# दैनिक जागरण

www.jagran.com
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और प. बंगाल से प्रकाशित

योगी के खिलाफ दंगा मामले में उचित आदेश पारित करें : सुप्रीम कोर्ट 2
ऋषभ पंत ने भी ठोका शतक 18

# आइजीआइ से वाया मानेसर जुड़ सकता है जेवर एयरपोर्ट

## एलिवेटेड रोड के निर्माण पर भारी भरकम लागत का अनुमान

जेवर एयरपोर्ट

**जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा :** जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मानेसर होकर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से जोड़ा जा सकता है। दोनों एयरपोर्ट को एलिवेटेड रोड से जोड़ने पर आने वाले भारी भरकम खर्च से बचने के लिए इस विकल्प पर काम हो सकता है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी पर सुझाव देने के लिए यमुना प्राधिकरण एजेंसी का चयन करेगा। इसके लिए इसी सप्ताह रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल निकाला जाएगा।

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सबसे अधिक यात्री दिल्ली एनसीआर से मिलने का अनुमान है, इसलिए एयरपोर्ट का निर्माण शुरू होने के साथ दिल्ली-एनसीआर से उसकी कनेक्टिविटी के लिए भी काम शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है। जेवर एयरपोर्ट को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी इसमें शामिल हैं। दोनों एयरपोर्ट के बीच यात्रियों की कम समय में आवाजाही संभव की जाएगी।

इसके लिए दोनों एयरपोर्ट के बीच एलिवेटिड रोड बनाने पर विचार शुरू हुआ था, लेकिन इसके निर्माण पर करीब 18 हजार करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। यमुना प्राधिकरण के लिए यह खर्च वहन करना आसान नहीं होगा,

जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली एनसीआर से मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के अध्ययन के लिए एजेंसी का चयन किया जाएगा। इसके लिए आरएफपी निकाला जाएगा। – डॉ. अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण

इसलिए आइजीआइ को ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे के रास्ते जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने का विचार भी सामने आया है।

मानेसर से आइजीआइ की दूरी करीब बीस किमी है। दोनों के बीच रोड बनने से आइजीआइ से आने वाले वाहन मानेसर ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पर चढ़ जाएंगे और यमुना एक्सप्रेस वे से होकर जेवर एयरपोर्ट तक आसानी से आ जा सकेंगे।

एलिवेटेड रोड की अपेक्षा इसकी लागत भी कम आने के अनुमान है। जेवर एयरपोर्ट के लिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए चयनित एजेंसी को इस पर भी सुझाव देना होगा। यमुना प्राधिकरण एजेंसी के चयन के लिए इसी सप्ताह आरएफपी निकालने जा रहा है। एजेंसी केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय एवं राज्य सरकार की गाइड लाइन के तहत जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली से जोड़ने के लिए पॉड टैक्सी, मेट्रीनो, हाइपर लूप, ट्राम, रैपिड बस ट्रांसपोर्ट के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगी। एजेंसी को ट्रांसपोर्ट मॉडल को विकसित करने में आने वाले खर्च, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश समेत एनसीआर के अन्य शहरों से मिलने वाले यात्रियों की अनुमानित संख्या, जेवर एयरपोर्ट व इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बीच होने वाली यात्रियों की आवाजाही पर रिपोर्ट देनी होगी। हालांकि, जेवर एयरपोर्ट को मेट्रो या रैपिड ट्रेन से जोड़ने लिए प्राधिकरण पहले ही डीएमआरसी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को जिम्मेदारी सौंप चुका है। हालांकि, उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही एयरपोर्ट की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी।

### नवरात्र में शिलान्यास की अटकलें

जेवर एयरपोर्ट की जमीन अधिग्रहण की अड़चन दूर हो चुकी है। इसके साथ ही अटकलें लगानी शुरू हो गई हैं कि अक्टूबर मे नवरात्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कर सकते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय ने जेवर एयरपोर्ट की प्रगति की जानकारी भी ली थी। नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो का उद्घाटन भी अक्टूबर में प्रस्तावित है। चर्चा शुरू हो गई है कि मेट्रो के उद्घाटन के साथ ही जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास भी हो जाएगा। हालांकि अधिकारी इस संबंध में कुछ भी कहने को तैयार नहीं हैं, लेकिन जिस तेजी से जेवर एयरपोर्ट से जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। उससे एयरपोर्ट के जल्द शिलान्यास की अटकलें सही साबित हो सकती हैं।

## जेवर एयरपोर्ट के लिए भू अर्जन प्रस्ताव होगा संशोधित

**जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा :** जेवर एयरपोर्ट के भू-अर्जन प्रस्ताव को संशोधित किया जाएगा। सोशल इंपेक्ट ऐससमेंट एसआइए के लिए गठित विशेषज्ञ समूह की बैठक में दो गांवों को जेवर एयरपोर्ट के अधिग्रहण से बाहर करने पर सहमति बनी थी, इसलिए भू-अर्जन प्रस्ताव में संशोधन की जरूरत पड़ रही है। यमुना प्राधिकरण संशोधित भू-अर्जन प्रस्ताव प्रशासन को भेजेगा।

जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण के लिए पूर्व में आठ गांवों के भू-अर्जन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। इसमें रोही, पारोही, किशोरपुर, दयानतपुर, रामनेर, रन्हेरा, मुकीमपुर सिवारा, बनबारीवास शामिल थे। गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय की टीम ने इन सभी गांवों में जेवर एयरपोर्ट परियोजना के प्रभाव के लिए सोशल इंपेक्ट ऐससमेंट किया था। एसआइए के मूल्यांकन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह ने एयरपोर्ट के पहले चरण में जमीन की कम से कम जरूरत को देखते हुए रामनेर व मुकीमपुर सिवारा को अधिग्रहण से बाहर कर दिया, लेकिन इस प्रस्ताव को जिला प्रशासन को नहीं भेजा गया था। इसलिए जिला प्रशासन की नजर में जमीन अधिग्रहण पर सहमति के लिए प्रभावित परिवारों की संख्या अधिक बैठ रही है। प्रशासन की ओर से सहमति के लिए जारी सार्वजनिक सूचना में भी आठ गांवों का जिक्र हो रहा है। सोमवार को गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में हुई बैठक में भू- अर्जन का संशोधित प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजने का निर्णय लिया गया।

एयरपोर्ट से 5926 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। दयानतपुर से 797, रोही से 919 व किशोरपुर से 59 परिवार विस्थापित होंगे। जिला प्रशासन इसी सप्ताह धारा 11 (जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना) का प्रस्ताव तैयार कर लेगा। किसानों की सहमति का आंकड़ा पूरा होते ही इस प्रस्ताव को शासन को भेज दिया जाएगा। पचास करोड़ से अधिक की लागत वाली परियोजना के लिए शासन से धारा 11 की अधिसूचना जारी होना जरूरी है। इसके मद्देनजर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी से भी समय मांगा जा रहा है, ताकि जिला प्रशासन से भेजे गए धारा 11 के प्रस्ताव पर शासन स्तर से जल्द अधिसूचना जारी हो सके।

### 3600 किसान लगा चुके हैं सहमति पर मुहर

**जासं, ग्रेटर नोएडा :** जेवर एयरपोर्ट के लिए प्रथम चरण में जमीन अधिग्रहण में अब कोई बाधा बाकी नहीं रही है। 1334 हेक्टेयर में 1145 हेक्टेयर के लिए 3600 किसान अपनी सहमति दे चुके हैं। जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने दावा किया है कि मंगलवार तक जेवर एयरपोर्ट के पहले चरण के लिए 94 फीसद जमीन के लिए किसानों से सहमति मिल गई है। प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी गावों में जाकर किसानों की सहमति ले रहे हैं। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत सत्तर फीसद की सहमति मिलने के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। इसलिए जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह, जिला प्रशासन व यमुना प्राधिकरण किसानों की सहमति के लिए प्रयास में जुटे हैं। एयरपोर्ट के लिए जमीन पर सहमति का आंकड़ा हालांकि 94 फीसद हो गया है, लेकिन प्रभावित किसानों की संख्या अभी कम है। इसलिए परियोजना में किसानों की सहमति का आंकड़ा बढाने की कोशिश हो रही है। इसी सप्ताह सत्तर फीसद का आंकड़ा पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है।

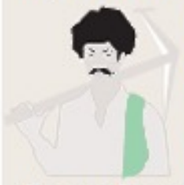

### प्रस्ताव

- 1145 हेक्टेयर के लिए मिली किसानों की सहमति
- जमीन अधिग्रहण में अब नहीं कोई बाधा